नवाचार सूचकांक में यूपी सातवें स्थान पर

नई दिल्ली, एजेंसी। नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक (इनोवेशन इंडेक्स) में हरियाणा तीसरे और उत्तर प्रदेश सातवें स्थान पर है। कर्नाटक लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने गुरुवार को सूचकांक रिपोर्ट जारी की।

17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को 16.35 अंक प्राप्त हुए हैं। पिछली बार यह छठे स्थान पर था। 14.22 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश इस बार भी शीर्ष 10 में जगह बनाने में कामयाब हुआ और दो पायदन की बढ़त भी हासिल की। कर्नाटक को सबसे ज्यादा 18.01 अंक हासिल हुए, वहीं तेलंगाना ने दूसरे स्थान पर बाजी मारी। सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार हैं। छत्तीसगढ़ को सबसे कम 10.97 अंक मिले। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में औसत अंक 14.02 रहे। भारत नवाचार सूचकांक, 2021 में राज्यों के स्तर पर नवाचार क्षमताओं और परिवेश की पड़ताल की गई है।

सूचकांक के मुताबिक, यूपी और हरियाणा ने इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ ही निवेश के लिए सुरक्षित परिवेश और नवोन्मेषी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नीति आयोगपरमेश्वरन अय्यर, आयोग देश में राज्यों के नवाचार पर निगरानी रखने को प्रतिबद्ध है।

प्रदेशों को ऐसे किया वर्गीकृत

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

चंडीगढ़ से पिछड़ा दिल्ली

केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में 27.88 अंकों के साथ चंडीगढ़ ने दिल्ली को पछाड़ दिया है। पिछली बार पहले स्थान पर रहने वाली दिल्ली 27 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, 5.91 अंकों के साथ लद्दाख को नौवां स्थान मिला है।

पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर

पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में 17.67 अंकों के साथ उत्तराखंड इस बार भी दूसरे स्थान पर है। वहीं, मणिपुर शीर्ष पर और मेघालय तीसरे स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश को इस बार पांचवें स्थान पर संतोष करना पड़ा, जबकि पिछली बार वह इस श्रेणी में शीर्ष पर था। 11 अंकों के साथ नगालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा।

इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल

नीति आयोग ने कहा, पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। सूचकांक का तीसरा संस्करण देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूत करता है। सूचकांक के पहले और दूसरे संस्करण को अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।